(घ)

खंड	स्थान	संबद्ध व्यक्तियों की संख्या
सहारनपुर-देहरादून	उप मुख्य इंजीनियर/ निर्माण, गाजियाबाद	मुख्य इंजीनियर/सर्वेक्षण के अधीन उत्तर रेल का
देहरादून-ऋषिकेश	-वही-	सर्वेक्षण संगठन तथा व्यावसायिक
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग	उप मुख्य इंजीनियर/सर्वेक्षण, नई दिल्ली तथा अपने फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से रूड़की विश्वविद्यालय	यूनिटों जैसे रूड़की विश्वविद्यालय आदि द्वारा भी सहायता की गई है।

(ङ) जी नहीं।

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव

*600. **श्री ओम प्रकाश कोहली:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आरंभ की गई 'मध्याह्न भोजन योजना' का क्या प्रभाव पड़ा है तथा इससे यह कहां तक सुनिश्चित हुआ है कि इन स्कूलों में नियमित उपस्थिति बनी रहे और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में कमी आए;

(ख) क्या सरकार ने इस दृष्टि से इस योजना के संबंध में कोई समीक्षा कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना की समीक्षा कराने का इरादा रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) से (घ) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति को बढ़ावा तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के आहार पर प्रभाव डालकर प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था। वर्ष 1997-98 में, यह योजना 507 जिलों के 5440 ब्लाकों के लगभग 6 लाख स्कूलों में 8.68 करोड़ बच्चों को शामिल करने तक ही सीमित है।

चूंकि यह योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है अतः बच्चों की उपस्थिति तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, अभी तक कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं कराया गया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों ही द्वारा की जाती है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उन्हें देखने से पता चला है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Subsidies to Farmers

4424. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the different types of indirect and direct subsidies being given to farmers and their annual impact;

(b) which of these are oriented towards small and marginal farmers and poorer sections of the farming population;

(c) whether any study has been undertaken to verify whether such subsidies reach the targeted populatin; if so, the results thereof; and

(d) if not, in what manner it is ensured that these subsidies actually reach the targeted population?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Major agricultural input subsidies given to farmers are fertilizers, irrigation, power and credit subsidy. Direct subsidy on urea is given by the Central Government to manufacturers of fertilizers to enable them to make available the fertilizer at reduced rates to the farmers. Urea is subsidised and sold at a uniform price of Rs. 3660/- per tonne throughout the country. In addition the Department of Agriculture & Cooperation is implementing, from Rabi 1992-93, a scheme of concessioin on sale of phosphatic and potassic (p&k) fertilizers to the farmers on the following:

(Rs. per tonne)

Product	*Rate of concession from* 1.4.1997
Indigenous DAP	3750
Imported DAP	2250
MOP	2000
SSP	600
Indigenous complexes	1149—2320

Since there is no mechanism to pay directly to the farmers, the subsidy/ concession is routed through the fertilizer suppliers. The provision in RE 1996-97 and in BE 1997-98 for the payment of subsidy on urea and concesson on p&k fertilizers is given below:

(Rs. in crores)

	Subsidy on Urea	*Concession on p&k fertilizers*
RE 1996-97	6093	1674
BE 1997-98 (proposed)	7190	2000

Subsidies on irrigation and power are given indirectly by the state Government charging lower rates thatn that of actual costs.

All these subsidies/concession are available to all the categories of farmers including small and marginal farmers.

(c) and (d) No study has been conducted to verify whether such subsidies/concessions reach to the targeted population. However, it is not practically feasible to pay the subsidies/ concessions directly to the farmers whose number is nearly 105 millioin and spread over the length and breadth of the country. All the policy guidelines for payment of subsidies/concessions are done keeping in view the interest of the farmers.

Subsidy to Farmers of Punjab for ensuing Kharif Season

4425. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal tc give subsidy to farmers of Punjab by Government to enhance the yield of cotton and paddy during the coming Kharif season; and

(b) if so, the amount being given to Government of Punjab for this purpose?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Incentives are being provided to the farmers of Punjab for increasing the productivity and production of cotton and paddy under Centrally Sponsored schemes on Intensive Cotton Development Programme and Integrated Cereals Developoment Programme in Wheat Based Cropping System Areas respectively. The Schemes are proposed to be continued during 1997-98 with a proposed alloeation of over Rs. 600 Lakhs.